



‘मातृछाया’ ने आचार्य पाठशाला में जरूरतमंद युवतियों के लिए 10 सिलाई मशीनें भेंट की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूर। ‘मातृछाया’ जैन महिला संगठन ने एनआरए कॉलोनी स्थित आचार्य पाठशाला एज्युकेशनल ट्रस्ट को 10 सिलाई मशीनें भेंट की। अध्यक्ष ललिता नागोरी ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि कौशल प्रशिक्षण देकर शिक्षा के साथ कमाई करने की दिशा में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 10 सिलाई मशीनें भेंट की गई हैं।

मार्गदर्शिका त्रिशला कोठारी ने कहा कि आत्मनिर्भरता ही सशक्तिकरण की पहली सीढ़ी है। हम चाहते हैं कि ये छात्राएं केवल शिक्षा में ही नहीं, बल्कि कौशल में भी अग्रणी बनें। अतिथि ललिता सिंघवी, लता बोहरा, संगीता सेठिया ने मातृछाया के मानवसेवी कार्य की सराहना की। आचार्य पाठशाला एज्युकेशनल ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ विष्णुभरत एवं सचिव प्रकाश ने ‘संस्था को धन्यवाद दिया। सचिव रेशमा बड़ोला ने बताया कि इन सिलाई मशीनों के उद्घाटन के साथ ही छात्राओं के लिए कॉलेज द्वारा निःशुल्क फैशन डिजाइनिंग कोर्स प्रारम्भ किया जाएगा। प्रधानाचार्य ने कहा कि इन सिलाई मशीनों का पूरा उपयोग हो इसलिए इसे हमारे शैक्षणिक पाठ्यक्रम में ही जोड़ेंगे एवं प्रति तीन माह में सिलाई मशीन प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस मौके पर कोषाध्यक्ष पुष्पा बाफना, प्रोजेक्ट संयोजिका कविता जैन निर्मला दातेवाड़िया, पुष्पा सोनीनारा हेमाबंदा, त्रिशला दातेवाड़िया, पुष्पा नागोरी सहित अनेक सदस्यएं उपस्थित थीं।



सरकारी निगम-बोर्ड में जैन समाज को उचित प्रतिनिधित्व मिले : प्रवीण बाफना

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूर। जीतो कर्नाटक, केरल एवं गोवा जौन के अध्यक्ष प्रवीण बाफना के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने कर्नाटक सरकार के विधान परिषद सदस्य व कर्नाटक कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग अध्यक्ष के. अब्दुल जब्बार से शिष्टाचार भेंट की। बाफना ने राजनेता को बताया कि कर्नाटक का जैन समाज राज्य की जरूरतमंद जनता की सेवा में हमेशा ही अग्रणी भूमिका में रहा है। उन्होंने कोरोना काल में जैन समाज द्वारा की गई मानवसेवा कार्य की जानकारी दी। उन्होंने अब्दुल जब्बार से कहा कि आज जैन समाज सरकारी प्रबंधन में शामिल होकर जनता के प्रति अपनी सेवाओं को विस्तार देना चाहता है अतः निगम बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा जैन प्रतिनिधियों को सम्मिलित करने की जीतो की मांग सरकार तक पहुंचाएं। प्रतिनिधि मंडल ने सरकारी निगम-बोर्ड में जैन समाज को जोड़ने के साथ कर्नाटक के सभी जिलों में संवाचित प्रधानमंत्री 15 सूत्री योजना में सदस्य के रूप सेवा देने का अवसर प्रदान करवाने का भी अनुरोध किया। प्रतिनिधि मंडल में सम्मिलित कर्नाटक अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश सचिव व जीतो बेंगलूर नार्थ के उपाध्यक्ष कमल पुनमिया, जीतो केकेजी जौन के माइनोंरिटी एवं मीडिया प्रभारी सिद्धार्थ बोहरा, जीतो केकेजी जौन सीएफई संयोजक नितिन कटारिया, जीतो जैन बंधु योजना समिति सदस्य अमित कोठारी एवं समाज सेवी ताराचंद गुगलिया उपस्थित थे। भेंट के दौरान कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम के निदेशक मोहम्मद सिराज तथा कर्नाटक अल्पसंख्यक कांग्रेस के एडमिन इश्शाद अहमद शेख उपस्थित थे।



न्यायालय का 1984 भोपाल गैस त्रासदी से जुड़ी याचिका पर विचार करने से इनकार

नई दिल्ली/भाषा। उद्यतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि 1984 की भोपाल गैस त्रासदी में गंभीर रूप से घायल हुए कई लोगों को कम मुआवजा दिया गया, क्योंकि उन्हें अस्थायी विकलांग या मामूली रूप से घायल व्यक्ति के तौर पर गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया था। प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने याचिकाकर्ता संगठनों को इस मामले में संबंधित उच्च न्यायालय का रुख करने की स्वतंत्रता दे दी। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि उद्यतम न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर विचार नहीं किया है। भोपाल में न्यूनियन कार्बाइड के कारखाने से 2-3 दिसंबर, 1984 की दरम्यानी रात अत्यधिक विषैली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ, जिसके बाद 5,479 लोगों की मौत हो गई और पांच लाख से ज्यादा लोग अंग्ग हो गए। इसे दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक आपदाओं में से एक माना जाता है। जब मामला पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया, तो प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि दशकों बीत चुके हैं। याचिकाकर्ता संगठनों के कहील ने कहा कि उन्होंने याचिका में सीमित अनुरोध किया है और वह किसी मामले को पुनः खोलने की मांग नहीं कर रहे हैं।

गाजा पर सरकार की चुप्पी जिंदनीय, कभी इतनी “नैतिक कायरता” नहीं दिखी : कांग्रेस

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि मोदी सरकार गाजा की स्थिति को लेकर चुप है ताकि इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू नाराज न हो जाएं। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि भारत सरकार ने कभी इतनी “नैतिक कायरता” नहीं दिखायी थी। रमेश ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, “गाजा में फलस्तीनी लोगों पर इजराइली प्रशासन द्वारा भयावह अत्याचार लगातार जारी है। जरूरी खाद्यपदार्थ जैसी मानवीय मदद लेने जा रहे लोगों को बेरहमी से मार दिया जा रहा है या उन्हें जान-बूझकर भूखा रखा जा रहा है। यह सुनिश्चित रूप से अंजाम दिया जा रहा एक निर्मम जनसंहार है, जिसमें पूरे समुदाय को मिटाने की कोशिश की जा रही है।” उन्होंने आरोप लगाया, “इसके बावजूद मोदी सरकार पूरी तरह चुप है और प्रधानमंत्री इसलिए पूरी तरह उदासीन बने हुए हैं ताकि उनके मित्र बेंजामिन नेतन्याहू नाराज न हो जाएं। भारत सरकार ने कभी इतनी नैतिक कायरता नहीं दिखायी।” रमेश ने कहा कि यह बेहद शर्मनाक और अत्यंत निंदनीय है। उधर, भारत ने गाजा में जारी मानवीय संकट पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वहां संघर्षविराम जरूरी है और यह भी स्पष्ट किया कि “बीच-बीच में संघर्षविराम” क्षेत्र की जनता के सामने मौजूद चुनौतियों को दूर करने के लिए “पर्याप्त नहीं” हैं।

भारत-ब्रिटेन एफटीए देश के उभरते व्यापार ढांचे में मील का पत्थर: उद्योग जगत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भारतीय उद्योग जगत ने बृहस्पतिवार को कहा कि यह भारतीय निर्यातकों के लिए परिवर्तनकारी पल है और इससे दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार मौजूदा 60 अरब डॉलर से 2030 में दोगुना होकर 120 अरब डॉलर का हो जाएगा। उद्योग जगत ने ऐतिहासिक एफटीए का स्वागत करते हुए कहा कि इससे दोनों देशों को लाभ होगा, क्योंकि इससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और उद्यमिता के लिए अधिक रोजगार तथा अवसर पैदा होंगे। एफटीए से ब्रिटेन को 99 प्रतिशत भारतीय निर्यात पर शुल्क कम हो जाएगा, जबकि ब्रिटिश कंपनियों के लिए भारत को व्हिस्की, कार और अन्य उत्पादों का निर्यात आसान हो जाएगा। भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ (फियो) के अध्यक्ष एस सी रहलन ने भारत-ब्रिटेन एफटीए पर कहा कि यह भारतीय निर्यातकों के लिए परिवर्तनकारी पल है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार मौजूदा 60 अरब डॉलर से 2030 में दोगुना होकर 120 अरब डॉलर का हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत-ब्रिटेन एफटीए प्रमुख क्षेत्रों, विशेष रूप से एमएसएमई और श्रम-प्रधान उद्योगों के लिए अभूतपूर्व अवसर खोलेगा। यह न सिर्फ शुल्क कम करता है, बल्कि सेवाओं और निवेश के लिए नियामक बाधाओं को भी कम करेगा। रहलन ने कहा, “एफटीए से भारत के विनिर्माण और सेवा निर्यात को काफी बढ़ावा मिलेगा तथा प्रमुख क्षेत्रों में ब्रिटेन से निवेश आकर्षित होगा।” फिक्की के अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल ने कहा कि भारत-ब्रिटेन एफटीए पर हस्ताक्षर भारत के उभरते व्यापार ढांचे में मील का पत्थर है, जो गहन वैश्विक आर्थिक एकीकरण के उसके दृष्टिकोण के अनुरूप है। यह घरेलू उद्योगों को वैश्विक स्तर पर विस्तार करने, प्रतिस्पर्धात्मक रूप से जुड़ने और मूल्य शृंखलाओं का अधिक प्रभावी ढंग से लाभ उठाने के लिए सशक्त बनाकर आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों को पूरा करता है।

भारत तीन प्रकार के छोटे मॉड्यूलर रिफ़क्टर विकसित कर रहा : जितेंद्र

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भारत तीन प्रकार के छोटे मॉड्यूलर रिफ़क्टर (एसएमआर) विकसित कर रहा है, जिनमें से एक रिफ़क्टर विशेष रूप से हाइड्रोजन उत्पादन के लिए होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा को एक लिखित उत्तर यह जानकारी देते हुए बताया कि ये रिफ़क्टर मुख्यतः ऊर्जा-गहन उद्योगों के लिए कैप्टिव प्लांट्स के रूप में इस्तेमाल किए जाएंगे। सिंह ने बताया कि भारत में स्वदेशी रूप से तीन प्रकार के एसएमआर विकसित किए जा रहे हैं। इनमें 200 मेगावाट विद्युत क्षमता वाला भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिफ़क्टर (बीएसएमआर-200), 55 मेगावाट क्षमता वाला एसएमआर, और पांच मेगावाट थर्मल उच्च तापमान गैस कूल्ड रिफ़क्टर (जीसीआर) शामिल हैं। उन्होंने बताया कि पांच मेगावाट थर्मल उच्च तापमान गैस कूल्ड रिफ़क्टर (जीसीआर) को विशेष रूप से हाइड्रोजन उत्पादन के लिए डिज़ाइन किया गया है। डॉ. सिंह ने कहा कि इन रिफ़क्टरों के निर्माण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त हो चुकी है, और परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के 60 से 72 महीनों के भीतर इनका निर्माण शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि

न्यायमूर्ति वर्मा के मामले में जांच समिति गठित करने की घोषणा कर सकते हैं बिरला: सूत्र

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों के आधार की पड़ताल के लिए एक जांच समिति गठित करने की घोषणा कर सकते हैं। सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि 21 जुलाई को बिरला को सौंपा गया 152 सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस अब “सदन का दस्तावेज” है और

उच्च सदन भी परामर्श प्रक्रिया का हिस्सा है। इस प्रक्रिया के तहत, अध्यक्ष द्वारा प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) को प्र को प्र लिखकर दोनों न्यायाधीशों के नाम के लिए उनकी अनुशंसा प्राप्त करने की उम्मीद है, जबकि प्रतिष्ठित न्यायविद का चयन उनका विशेषाधिकार है। नोटिस सौंपे जाने के बाद से, गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा के सदन के नेता जे पी नड्डा, लोकसभा अध्यक्ष बिरला और राज्यसभा के



कंगना ने अमित शाह से मुलाकात की

हिमाचल में हुई भीषण बारिश और बाढ़ के बारे में जानकारी साझा की

नई दिल्ली/भाषा। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि हिमाचल प्रदेश में बाढ़ प्रभावित सभी लोगों को हरसंभव सहायता और शीघ्र पुनर्वास प्रदान किया जाएगा। मंत्री से सांसद रनौत ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “आज नई दिल्ली में माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात कर मंडी लोकसभा क्षेत्र में हाल ही में आई भयंकर प्राकृतिक आपदा की विस्तृत जानकारी साझा की।” उन्होंने कहा, “मंत्री जी ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए आश्वासन दिया कि सभी प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता और शीघ्र पुनर्वास प्रदान किया जाएगा। केंद्र सरकार इस संकट की घड़ी में हिमाचल के साथ मजबूती से खड़ी है।” हिमाचल प्रदेश में 22 जून को मानसून की शुरुआत के बाद से, राज्य भर में बारिश से संबंधित घटनाओं में कम से कम 76 लोगों की मौत हो गई है और 3.4 लापता हैं। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र (एसईओसी) के अनुसार, इस मानसून में राज्य में 40 बार अचानक बाढ़, 23 बार बाल फटने और 25 बार भूखलन की घटनाएं हुई हैं, जिससे लगभग 1,247 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।

गोवा विस में खूंखार जानवरों के प्रजनन व पालन पर रोक संबंधी विधेयक पारित

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पणजी/भाषा। गोवा विधानसभा ने अदालतों के अधिकार क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए दीवानी मुकदमों विशेष रूप से भूमि से संबंधित मुकदमों के मूल्यांकन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और खूंखार घोषित किए गए जानवरों के प्रजनन और पालन पर रोक लगाने संबंधी विधेयक पारित किया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मुकदमों के मूल्यांकन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने संबंधी विधेयक बुधवार को सदन में पारित होने के अवसर पर कहा कि ‘गोवा वाद मूल्यांकन विधेयक, 2025’ राज्य सरकार को उच्च न्यायालय के परामर्श से विभिन्न क्षेत्रों में भूमि मूल्य निर्धारण के उद्देश्य से नियम बनाने का अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि अधिकार क्षेत्र और शुल्कों से संबंधित विवादों और भ्रम को कम करने के लिए मूल्यांकन में एकरूपता आवश्यक है। मुख्यमंत्री सावंत द्वारा सदन में प्रस्तुत यह विधेयक, मूल्यांकन प्रक्रिया को हाल ही में पारित गोवा न्यायालय



शुल्क अधिनियम, 2024 के अनुरूप बनाने का प्रयास करता है और यह गोवा वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1965 का स्थान लेगा। गोवा विधानसभा ने खूंखार घोषित किए गए जानवरों के प्रजनन और पालतू बनाने पर रोक लगाने संबंधी एक विधेयक बुधवार को पारित किया जिसमें ऐसे पशुओं के हमलों की स्थिति में मुआवजे और उल्लंघन के आरोप में तीन महीने तक की कैद की सजा का प्रावधान है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को विधानसभा में बताया कि राज्य में ‘पिटबुल’ और ‘रॉटवीलर’ जैसी खूंखार नस्ल के कुत्तों द्वारा बच्चों को काटने के मामले सामने आने के बाद ‘गोवा पशु प्रजनन और पालन (विनियमन और मुआवजा) विधेयक, 2025’ पेश किया गया है।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

एफटीए में डेयरी उत्पाद, खाद्य तेल, सेब शामिल नहीं, 95 प्रतिशत कृषि निर्यात शुल्क-मुक्त

नई दिल्ली/भाषा। भारत ने ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) में डेयरी उत्पादों, खाद्य तेल और सेब को शामिल नहीं किया है, जो घरेलू किसानों के हित में हैं। इसके साथ ही 95 प्रतिशत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर शुल्क शुल्क सुनिश्चित किया है। बृहस्पतिवार को हस्ताक्षरित एफटीए में जई पर भी कोई शुल्क रियायत नहीं दी गई है। दूसरी ओर, हल्दी, काली मिर्च, इलायची जैसी भारतीय खाद्य वस्तुएं; आम का गुदा, अचार और दालें जैसी प्रसंस्कृत वस्तुएं; और झींगा और टूना जैसे समुद्री उत्पाद ब्रिटेन के बाजार में शुल्क-मुक्त पहुंच का लाभ लेंगे। कृषि के क्षेत्र में ब्रिटेन 37.52 अरब डॉलर मूल्य के उत्पादों का आयात करता है, जबकि भारत से आयात केवल 81.1 करोड़ डॉलर का ही होता है। वाणिज्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, “भारत के किसान मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के सबसे बड़े लाभार्थी बनने के लिए तैयार हैं, जो उनके उत्पादों के लिए प्रीमियम ब्रिटिश बाजारों को खोलेगा। इससे उन्हें जर्मनी, नीदरलैंड और अन्य यूरोपीय संघ के देशों के निर्यातकों को पहले से मिल रहे लाभ के बराबर या उससे भी फायदा मिलेगा।”



अमरनाथ यात्रा: जम्मू आधार शिविर से 3,500 श्रद्धालुओं का जत्था रवाना

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जम्मू/भाषा। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से बृहस्पतिवार को 3,500 श्रद्धालुओं का नया जत्था दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के लिए रवाना हुआ। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, 22वें जत्थे में 2,704 पुरुष, 675 महिलाएं, 12 बच्चे और 109 साधु-साधवियां शामिल हैं। यह जत्था कड़ी सुखा व्यवस्था के बीच 140 वाहनों के दो काफिलों में पहलगाम और बालटाल मार्ग के लिए रवाना हुआ। इनमें से 2,668 श्रद्धालु 95 वाहनों के काफिले में पहलगाम मार्ग के लिए जबकि 45 वाहनों के काफिले में 832 श्रद्धालु बालटाल मार्ग के लिए रवाना हुए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा दो जुलाई को पहले जत्थे को रवाना किए जाने के बाद से अब तक 1,33,878 श्रद्धालु जम्मू आधार शिविर से कश्मीर के लिए रवाना हो चुके हैं। तीन जुलाई से शुरू हुई 38 दिवसीय वार्षिक अमरनाथ यात्रा के दौरान अब तक 3.40 लाख से अधिक श्रद्धालु 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक हिम शिखरों के दर्शन कर चुके हैं। पिछले वर्ष 5.10 लाख श्रद्धालुओं ने गुफा मंदिर में दर्शन किए थे।

ब्रिटेन के साथ भगोड़ा प्रत्यर्पण समझौते की भी जरूरत: कांग्रेस

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस ने भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर से पहले बृहस्पतिवार को कहा कि विजय माल्या, नीरव मोदी और ललित मोदी जैसे लोगों को भारत वापस लाने के लिए “भगोड़ा प्रत्यर्पण समझौता” की भी जरूरत है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कटाक्ष किया कि मोदी सरकार की “भगोड़ानॉमिक्स” के ये तीन बड़े सितारे अपनी घर वापसी का इंतजार कर रहे हैं। भारत और ब्रिटेन बृहस्पतिवार को लंदन में एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। इससे श्रम-प्रधान उत्पादों जैसे चमड़ा, जूते और कपड़ों का रियायती दशों पर निर्यात संभव होगा जबकि ब्रिटेन से

इस साल 21 जुलाई तक विमानों में 183 तकनीकी खामियों की सूचना मिली : सरकार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि पांच भारतीय एयरलाइन ने इस साल 21 जुलाई तक अपने विमानों में 183 तकनीकी खामियों की सूचना विमान नियामक डीजीसीए को दी, जिनमें एअर इंडिया समूह के विमानन सेवाओं की 85 खामियां शामिल हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा बृहस्पतिवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, इंडिगो और आकाशा एअर ने क्रमशः 62 और 28 तकनीकी खामियों की सूचना दी, जबकि स्पाइसजेट ने 8 खामियों की सूचना दी। एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस ने कुल मिलाकर 85 तकनीकी खामियों की सूचना दी। ये सभी आंकड़े इस साल 21 जुलाई तक के हैं। वर्ष 2024 में दर्ज की गई तकनीकी खामियों की संख्या 421 थी, जो 2023 में रिपोर्ट की गई 448 से कम है। 2022 में रिपोर्ट की गई तकनीकी खामियों की संख्या 528 थी। इन तीन वर्षों के आंकड़ों में एलायंस एअर और पूर्ववर्ती वित्तारा के आंकड़े भी शामिल हैं।

देवनानी ने सिंदूर का पौधा लगाकर कारगिल शौर्य वाटिका में पौधारोपण का किया शुभारम्भ

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने उनकी पहल पर ही विधानसभा में बनाई गई कारगिल शौर्य वाटिका में गुरुवार को सिंदूर का पौधा लगाकर पौधारोपण का शुभारंभ किया।



देवनानी ने विधानसभा में तैयार की गई कारगिल शौर्य वाटिका में ह रियाली अमावस्या पर एक दिन में पांच प्रजातियों के 1100 पौधे लगाने की सिंदूर का पौधा लगाकर शुरूआत की। कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर देवनानी के साथ वीरगंगाओं ने भी विधानसभा की कारगिल शौर्य वाटिका में पौधे लगाये। इस मौके पर सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, वन एवं पर्यावरण मंत्री

संजय शर्मा, सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर तथा कई विधायकों ने भी वाटिका में पौधारोपण किया।

देवनानी ने बताया कि विधानसभा परिसर में कारगिल विजय में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में कारगिल शौर्य वाटिका की स्थापना की गई है। उन्होंने बताया कि इस वाटिका में सिंदूर, एरिका पाम, सांग ऑफ इण्डिया, किसना फाइडस और क्रोटोन प्रजाति के पौधे लगाये गये हैं। उन्होंने बताया कि वायु प्रदूषण को कम करने वाले यह पौधे भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सुंदरता के प्रतीक हैं। सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनाने वाले इन पौधों की पत्तियों का उपयोग पारम्परिक चिकित्सा प्रणाली में उपयोग किया जाता है। उन्होंने बताया कि कारगिल युद्ध जो 1999 में कारगिल सेक्टर में लड़ा गया था, वह भारतीय सेना के साहस और बलिदान का महत्वपूर्ण उदाहरण है। शौर्य वाटिका इस युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की वीरता को समर्पित है।

‘राजस्थान विश्वविद्यालय’ के विद्यार्थियों के एक समूह ने पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत से मुलाकात की

जयपुर/दक्षिण भारत। राजस्थान विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के एक समूह ने बृहस्पतिवार को यहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर राज्य में छात्र संघ चुनावों में हो रही देरी पर चिंता जताई। गहलोत ने कहा कि प्रदेश में छात्र संघ चुनाव भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार (2003-2008) के कार्यकाल के दौरान स्थगित कर दिए गए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर 2010 में छात्र संघ चुनाव फिर से शुरू कर दिए गए थे। गहलोत ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में चुनाव एक बार फिर रोक दिए गए थे और तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 2022 में प्रक्रिया फिर से शुरू करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, 2023 में छात्र संघ चुनाव फिर से स्थगित कर दिए गए क्योंकि विधानसभा चुनावों और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के लिए कॉलेजों को अस्थायी रूप से अधिग्रहित कर लिया गया था। हालांकि दिसंबर 2023 में राज्य में भाजपा सरकार आई और उसने छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं किए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने छात्र संघ चुनाव दोबारा शुरू करने की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने पहले भी छात्र संघ चुनाव बहाल करने का मुद्दा उठाया है।



अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे लाभ और वास्तविक जरूरतमंद सशक्त हो : बागड़े

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बालोतरा। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े ने वंचितों को योजनाओं से जोड़ने पर जोर देते हुए निर्देश दिए हैं कि सभी योजनाओं का प्रचार-प्रसार इस प्रकार हो कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक भी लाभ पहुंचे और वास्तविक जरूरतमंद वर्ग सशक्त हो सके। बागड़े गुरुवार को बालोतरा के कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में यह निर्देश दिए।

उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की और स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी पात्र व्यक्ति इन योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।

उन्होंने योजनाओं के समयबद्ध और परिणामोन्मुखी क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया।

इस दौरान राज्यपाल ने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों को आवास योजना एवं अन्य योजनाओं का लाभ प्राथमिकता से देने को कहा। बैठक के दौरान बागड़े ने जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वामित्व योजना, मनरेगा, मुख्यमंत्री जल स्वायत्तबन अभियान, कुसुम योजना, मिशन हरियालो राजस्थान, राजीविका, डेयरी विकास एवं सहकारिता विभाग की योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिए कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों को आवास योजना एवं अन्य योजनाओं में प्राथमिकता के साथ लाभान्वित किया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में नई

शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों की बौद्धिक और शारीरिक क्षमता को एक साथ विकसित किया जाए। उन्होंने जिले के स्कूलों में खेल मैदानों की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली और छात्रवासों में व्यायामशाला एवं खेल सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान देने को कहा। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मिशन हरियालो राजस्थान को और अधिक प्रभावी बनाने के भी उन्होंने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केवल पौधे लगाने तक सीमित न रहा जाए बल्कि उनकी सुरक्षा और सार-संभाल भी सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने कम जल आवश्यकता वाले पौधों के रोपण को प्राथमिकता देने को कहा ताकि पर्यावरणीय संतुलन के साथ जल संरक्षण भी संभव हो सके। उन्होंने मुख्यमंत्री जल स्वायत्तबन योजना की समीक्षा करते हुए जल संचयन एवं भूजल

स्तर बढ़ाने की दिशा में स्थानीय समाधान अपनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (राजीविका) के तहत महिला समूहों के उत्पादों की मार्केटिंग बढ़ाई जाए और प्रत्येक महिला को उद्यमिता के लिए प्रेरित किया जाए।

निष्क्रिय समूहों को पुनः सक्रिय करने और स्थानीय उत्पादों को आमजन तक पहुंचाने की दिशा में प्रभावी प्रयास करने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने अंत में सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नियमित निगरानी करें और सुनिश्चित करें कि किसी भी योग्य नागरिक को योजनाओं से वंचित न रहना पड़े। उन्होंने कहा कि योजनाएं केवल आंकड़ों में नहीं बल्कि धरातल पर नजर आनी चाहिए।

पिता ने डेढ़ वर्षीय बेटे को बोरवेल में फेंका

जयपुर। राजस्थान के जयपुर जिले में एक पिता ने अपने डेढ़ वर्षीय बेटे को बोरवेल में कथित तौर पर फेंक दिया। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि जमवारागढ़ के दीपोला गांव में हुई इस घटना में बच्चे को बचाने के लिए बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार यह घटना बुधवार रात की है और स्थानीय लोगों से सूचना

मिलने के बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। जमवारागढ़ के थानाधिकारी रामपाल शर्मा ने बताया कि आरोपी ललित अपने बेटे की बीमारी और पत्नी के लंबे समय तक मायके में रहने जैसे कारणों से परेशान था। शर्मा ने बताया कि ललित (बुधवार को) एक चिकित्सक के पास गया और अपने बेटे के लिए दवाइयां लीं। उन्होंने बताया, आरोपी ने दावा किया कि उसके बेटे की

कल (बुधवार को) रात मौत हो गई और इसके बाद उसने उसे एक सफेद कपड़े में लपेटकर बोरवेल में फेंक दिया। उसने अपने भाई को इस बारे में बताया। जब स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी मिली, तो पुलिस को सूचित किया गया। राज्य आपदा मोचन बल की एक टीम बचाव अभियान में जुटी है। अधिकारी ने बताया, ललित को हिरासत में ले लिया गया।



कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत की केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान के पशुपालन एवं डेयरी गोपालन एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। कुमावत ने केंद्रीय पशुपालन मंत्री राजीव रंजन सिंह से भेंट कर उन्हें राजस्थान में पशुपालन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं नवाचारों की जानकारी दी। कुमावत ने विभाग द्वारा अब तक किए गए उल्लेखनीय कार्यों का संकलन 'प्रगति पुस्तिका' के रूप में भेंट कर केंद्रीय मंत्री का देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए ऐसे राजस्थान के लिए पशुपालन क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न आवश्यकताओं, योजनाओं में केंद्रीय अंश बढ़ाने तथा भावी सहयोग को लेकर विस्तृत चर्चा की एवं संबंधित मांगें उनके समक्ष प्रस्तुत की।

इसी क्रम में कुमावत ने केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी शिष्टाचार भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस अवसर पर कुमावत ने उन्हें राजस्थान सरकार द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं एवं विकासात्मक कार्यों की जानकारी प्रदान की। उन्होंने पशुपालन विभाग द्वारा अब तक किए गए कार्यों का विवरण प्रस्तुत करती पुस्तिका भी केंद्रीय मंत्री को भेंट की। कैबिनेट मंत्री कुमावत ने नई दिल्ली में पाली

लोकसभा से सांसद एवं 'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर गठित संयुक्त संसदीय समिति (गमंडु) के चेयरमैन पी. पी. चौधरी से भी शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान पाली लोकसभा सहित राजस्थान से जुड़े विभिन्न जनहित के विषयों पर सार्थक चर्चा की।

मंत्री जोराराम कुमावत ने बृहस्पतिवार को अपने दिल्ली प्रयास के दौरान नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में 23 जुलाई से 30 जुलाई तक चलने वाले तीजोत्सव और हस्तशिल्प मेले का अवलोकन किया। इस दौरान कुमावत ने कहा कि राजस्थानी कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्थानीय कारीगरों के उत्पादों का देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए ऐसे मेले मिल का पत्थर साबित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों की देश-विदेश में लगातार मांग बढ़ रही है और राज्य सरकार भी उन्हें बढ़ावा देने के प्रतिबद्ध है। कुमावत ने मेले में लगे स्टालों पर व्यक्तित्व जाकर राजीविका और रुड़ा के विक्रेता कारीगरों का उत्साहवर्धन किया तथा उनके उत्पादों की सराहना की। पत्रकारों से बात करते हुए जोराराम कुमावत ने कहा की राजधानी में राजस्थान की सरस डेयरी के दुग्ध उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है तथा बीकानेर हाउस में सरस पार्लर खोलने के लिए प्रयास किया जा रहे हैं।



समुद्रतटों, पहाड़ियों, नदियों वाला हरा-भरा सुंदर मनभावन देश है वियतनाम

आधुनिक गगनचुंबी इमारतों वाले हो ची मिन्ह शहर सहित अनेक ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्व वाले पर्यटन स्थल मौजूद

■ श्रीकांत पाराशर
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। दक्षिण पूर्व एशिया के हिंदचीन प्रायद्वीप के पूर्व भाग में स्थित है वियतनाम। इसकी सीमाओं पर चीन, लाओस, कंबोडिया तथा दक्षिण चीन सागर देश हैं। यहाँ बौद्ध धर्म का बोलबाला है जो यहाँ का प्रमुख धर्म है। वियतनाम की राजधानी हनोई शहर है लेकिन सबसे बड़ा शहर हो चो मिन्ह है।यह हमारा मित्र देश माना जाता है। भारत और वियतनाम के बीच सांस्कृतिक व आर्थिक संबंध सदियों पुराने हैं। यहां की मुद्रा का नाम डॉंग है जो भारतीय मुद्रा रुपये की तुलना में काफी सस्ती है। भारत के एक रुपये के बदेले लगभग 322 वियतनामी डॉंग मिलते हैं, जिन्हें वीएनडी कहा जाता है।

वियतनाम का इतिहास

बैसे तो वियतनाम का इतिहास 2700 वर्षों से अधिक कालखंड का है लेकिन उतना पीछे न जाएं तो भी यह देश 19 वीं सदी में फ्रांस का उपनिवेश बना और 20 वीं सदी के मध्य तक फ्रांसीसियों को इन्होंने खदेड़ कर देश से बाहर कर दिया। देश दो हिस्सों में बंट गया लेकिन आगे चलकर इसने सबसे ताकतवर देश अमेरिका के भी छक्के छुड़ा दिए। वर्ष 1986 में एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ और यहां आर्थिक व राजनीतिक सुधार आए। गत एक दशक में तो देश का आर्थिक विकास दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से अग्रसर होता दर्ज किया गया।

समुद्रतटों, नदियों वाला हरा-भरा देश

यहाँ की नदियाँ, पहाड़ियाँ, समुद्रतट, ग्रामीण व आधुनिक जीवन शैली आदि पर्यटकों को बहुत आकर्षित करते हैं। वियतनाम की राजधानी हनोई है लेकिन सबसे बड़ा और सुंदर शहर हो ची मिन्ह है। इसका नाम पहले सैगोन (या साइगोन) था, जिसे बदलकर यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी, साम्राज्यवादी नेता हो ची मिन्ह के नाम से रख दिया गया। हो ची मिन्ह में ऊँची ऊँची इमारतें, चौड़ी सड़कें हैं। साफ-सुथरा, सुंदर व आधुनिकता का प्रतीक शहर है। इमारतें आधुनिक वास्तुकला का नमूना हैं।

शहरी व ग्रामीण जीवनशैली

पूरे वियतनाम में वियतनामी भाषा चलती है। इसमें अधिकांश शब्द चीनी भाषा के हैं। केवल बड़े सितारा होटलों व रेस्टोरेंट्स में अंग्रेजी समझने वाले लोग हैं, बाकी टूटीफूटी अंग्रेजी व इशारों की भाषा से पर्यटकों का काम चल जाता है। मोटर साइकिल व स्कूटर का चलन ज्यादा है, चारपहिया वाहन अपेक्षाकृत कम हैं। बेरोजगारी की दर विश्व में सबसे कम है। वियतनाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। शराब व सिगरेट का प्रचलन खूब है। यहाँ के लोग स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक हैं। यहां मोटोपे का प्रशिक्षण 2 है। सो में से केवल दो लोग ही थोड़ी तौंद वाले दिख सकते हैं। यहां सामान्यतया समुद्री भोजन पसंद किया जाता है। नूडल्स, सूप, सब्जियां, सलाद पर जोर रहता है। यहां कालिटि चावल का उत्पादन होता है और उसी का उपभोग भी खूब होता है। यह देश काजू का सबसे बड़ा निर्यातक और चावल निर्यात में दूसरा स्थान रखता है। काफी में भी ब्राजील के बाद दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है। यहां के बड़े शहरों की नाइटलाइफ पर्यटकों को आकर्षित करती है तो दूर दराज के द्वीपों में रहने वाले

ग्रामीणों के रहन-सहन, उनका जीवनयापन भी पर्यटकों की दिलचस्पी का हिस्सा है। यहां देखने के लिए बहुत कुछ है।

पर्यटकों के लिए दर्शनीय स्थल

हो ची मिन्ह से लगभग 100 किमी दूर वुंग ताऊ समुद्रतटीय कस्बा है, जहाँ का नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य सहज ही आकर्षित करता है। एक तरफ हरी-भरी पहाड़ियाँ, तो दूसरी ओर समुद्र का लंबा तटा यहाँ अनेक धार्मिक स्थल भी हैं। वुंग ताऊ में पहाड़ी पर स्थित ईसा मसीह की 32 मीटर ऊँची प्रतिमा भी आकर्षण का केंद्र है। इसके अलावा व्हाइट विला है जिसे व्हाइट पैलेस भी कहते हैं। यह फ्रांसीसी गवर्नर्स का निवास होता था।

हो ची मिन्ह सिटी में सांस्कृतिक महत्व का ओपेरा हाउस है जहां विभिन्न संगंमचीय कार्यक्रम होते हैं । यहां होने वाला एओ शो बहुत लोकप्रिय है जो दिन में केवल एक बार होता है। हो ची मिन्ह में इंडिपेंडेंस हाउस की भव्य इमारत तथा वार मेमोरियल आदि दर्शनीय स्थल हैं । यहां फ्रांस और अमेरिका के साथ वियतनामी युद्ध के दौरान वियतनामियों द्वारा कैसे रणनीति बनाई जाती थी और कैसे उस पर अमल किया जाता था, उसकी कथा कहते दृश्य व हथियार दर्शित हैं।

शहर से लगभग 70 किमी दूर कु ची टनल्स की तो बात ही छोड़ दी जाए। वियतनामी युद्ध प्रणाली व सैनिकों के साहस की जीवंत कथा सुनाती इन गुफाओं को देखने से रोंगटे खड़े हुए बिना नहीं रह सकते। इनके अलावा मेकोंग डेल्टा क्षेत्र में पानी पर तैरते गाँवों की जीवनशैली से बहुत कुछ सीखने व समझने को मिलता है।

■ इन दर्शनीय स्थलों पर विस्तारपूर्वक अन्य लेखों में विवरण दिया जा सकेगा।

वियतनाम जाएं तो कैसे जाएं?

आजकल एशियाई देशों के पर्यटक विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशियन देश वियतनाम जाने को उत्सुक रहते हैं। वर्ष दर वर्ष यहां पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। गत वर्ष की बात करें तो 50 लाख भारतीय पर्यटकों ने वियतनाम की सैर की। दक्षिण भारत के शहरों से भी वियतनाम जाने वाले पर्यटकों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिसमें बेंगलूरु और हैदराबाद से वियतनाम के हो ची मिन्ह शहर तक सीधी विमान सेवा का उपलब्ध होना है। पर्यटकों को अच्छी विमानन सेवा उपलब्ध हो तो किसी भी देश का चयन करने में आसानी होती है और इसी दिशा में वियतनाम मूल की वियतजेट एयरलाइंस आजकल पर्यटकों की पसंदीदा एयरलाइन बनी हुई है।



वियतजेट है बेहद अनुकूल विकल्प

बेंगलूरु व हैदराबाद से हो ची मिन्ह शहर(जिसे वियतनाम की आर्थिक राजधानी कहा जाता है) के लिए वियतजेट की सीधी विमान सेवा उपलब्ध है। यह वियतनाम की सबसे बड़ी निजी एयरलाइन कंपनी है जो बहुत ही रियायती मूल्य पर बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराती है। इसका मुख्यालय वियतनाम की राजधानी हनोई शहर में है।बेंगलूरु से हो ची मिन्ह शहर के लिए

वियतजेट की समाह में चार बार सोम, बुध, शुक्र व रविवार को सीधी उड़ानें हैं जो लगभग 5 घंटे के आरामदायक सफर के साथ वियतनाम पहुंचा देती हैं। इसी प्रकार वापसी की सुविधाएं उपलब्ध हैं।हो ची मिन्ह वहां का सबसे बड़ा शहर है जिसकी तुलना आर्थिक दृष्टिकोण से मुंबई से कर सकते हैं। हो ची मिन्ह को केंद्र बिंदु बना कर बहुत सारे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक व मनोरंजन महत्व के पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया जा सकता है।

वियतजेट एयरलाइंस बेंगलूरु से हो ची मिन्ह शहर तक जाने और वापस लौटने का इकोनॉमी किराया महज लगभग 20 हजार रुपये तक लेती है। वर्तमान में कई तरह की रियायतें देने वाली यह कंपनी बिजनेस क्लास तथा स्काई बॉस जैसी सुविधाएं भी रियायती दरों पर उपलब्ध करा रही है। स्काई बॉस श्रेणी के यात्रियों को कई प्रीमियम सुविधाएं मिलती हैं।वियतनाम जाने के लिए पर्यटक वीजा लेना कोई मुश्किल भरा काम नहीं है। आसानी से आनलाइन आवेदन कर वीजा प्राप्त कर सकते हैं।

वियतजेट एयरलाइंस का दावा है कि यह दुनिया की एकमात्र सुरक्षा और उत्पाद रेटिंग वेबसाइट पर वर्ष 2018 व 2019 में 7 स्टार रेटिंग प्राप्त कर चुकी है। वियतजेट ने वर्ष 2025 के लिए विश्व की अल्ट्रा लो-कोस्ट कैरियर का खिताब भी जीता है।उनके कर्मचारी अपने ग्राहकों के प्रति बेहद विनम्र, सहयोगी एवं सेवाभावी हैं ।

